दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार, 15 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 167

लोकसभा में गूंजा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, जितेन्द्र सिंह ने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता केजे अल्फोंस ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर अजीब बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि 1.5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को सांप्रदायिक आधार पर, सत्तारूढ़ सरकार द्वारा, जो कांग्रेस या उसकी समर्थित सरकारें थीं, बाहर कर दिया गया था।

वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के कारण सब कुछ गलत हुआ है तो वह सार्वजनिक रूप से यह बात कहें। लोकसभा में केंद्र शाासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए राज्य मंत्री सिंह ने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी इस सदन में कहेगी कि वह अगर सत्ता में आई तब अनुच्छेद 370 वापस लायेगी? कांग्रेस इस मामले पर अपना विचार व्यक्त करके इस संबंध में सवाल पर विराम लगाए।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपमें ऐसा कहने का साहस नहीं है क्योंकि आपको जनभावना मालूम है। जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ था और इसके बाद विषयों को ठीक ढंग से नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को चुनिंदा तौर पर निशाना बनाया गया, एक की हत्या एवं हजारों को धमकाने की नीति अपनायी गई जिससे कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ा।

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इससे पहले वहां पर दहेज विरोधी कानून, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग अत्याचार निवारण कानून, सूचना का अधिकार कानून, भ्रष्टाचार निवारण कानून आदि नहीं लागू था और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही इन्हें वहां लागू किया गया । उन्होंने कहा कि अब वहां स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के प्रावधानों को लागू किया गया है जिससे स्थानीय निकाय कोष में 10 हजार करोड़ रूपये भेजा जा रहा है। जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले नौकरियों में भर्ती के लिये कोई व्यवस्थित नियम एवं प्रक्रियाओं का अभाव था। अब इन्हें व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में उद्योगों के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 50 हजार करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और इस संबंध में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। सिंह ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सीमापार से घुसपैठ में कमी आने का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2010 में जब कांग्रेस नीत संप्रग की सरकार थी तब जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के 489 प्रयास किये गए थे जो वर्ष 2014 में भाजपा नीत सरकार आने के वर्ष में घटकर 222 रह गये। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्ष 2021 में घुसपैठ के 77 प्रयास किये गए और इस वर्ष दो महीनों में ऐसे 4 प्रयास किये गए हैं। मंत्री ने कहा कि यह बहुत बड़ा परिवर्तन है।

हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच, हाई कोर्ट ने पिछले महीने ही मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में एक मुद्दे के रूप में उभरा था। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर हुई सुनवाई के दौरान छात्राओं की ओर से अधिवक्ता विनोद कुलकर्णी ने पीठ से अनुरोध किया था कि शुक्रवार को जुमा है, कृपया अभी के लिए छात्राओं को शुक्रवार के दिन हिजाब पहनने की अनुमति दे दीजिए। पीठ ने कहा कि ठीक है, हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे।

कर्नाटक में हिजाब विवाद का मुद्दा का काफी तुल पकड़ा था। हिजाब का विरोध और उसके समर्थन में हुए प्रदर्शन की वजह से कर्नाटक सरकार को स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ गया था। हालांकि, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोल दिया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली जा रही ट्रेन में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली जाने वाली लोकल ट्रेन के अंदर सोमवार सुबह को एक लावारिस बैग मिलने से दहशत फैल गई। डीसीपी रेलवे हरेंद्र सिंह ने बताया, ट्रेन नंबर 04406 को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर रोका गया और बम निरोधक दस्ते ने इसकी जांच की। उन्होंने बताया कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सिंह ने कहा, इससे धुंआ निकल रहा था जिससे कुछ देर के लिए दहशत की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, इसमें कोई बम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लावारिस बैग संभवत: किसी बढ़ई या मजदूर का हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कुछ औजार और कीलें थीं। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि, इससे पूर्व गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर फूल मंडी और फिर फरवरी महीने में सीमापुरी इलाके से बरामद हुए लावारिस बैगों में आरडीएक्स जैसे शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा कोरोना संक्रमित, मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 से जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को शुभकामनायें दीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को कोविड-19 से जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की शुभकामनायें दी हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक ट्वीट के प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि बराक ओबामा, आपको कोविड-19 से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करने तथा आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के लिये मेरी शुभकामनायें। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अगर आपने पहले से टीकाकरण नहीं कराया है, तो भी यह एक रिमांडर है, भले ही मामले कम हों। ओबामा 60 साल के हैं। उन्होंने 2009 से 2017 तक अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार, रविवार दोपहर तक अमेरिका में 7.9 करोड़ से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए और लगभग 967,000 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बराक ओबामा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।

क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा, देसी पिस्तौल और गोलियां बरामद

मुंबई (आरएनएस)। क्राइम ब्रांच ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भायखाला इलाके से छोटा राजन के गुर्गे अराफात आरिफ लोखंडवाला को गिरफ्तार किया। अराफात के पास से एक देसी पिस्तौल और 28 राउंड गोलियां बरामद की गई है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि छोटा राजन का गुर्गा अराफात भायखला आने वाला है। क्राइम ब्रांच की टीम ने अराफात को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और घात लगाकर बैठी रही। जैसे ही अराफात वहां पहुंचा, क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे धर दबोचा।

दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने महिला और बेटे को घर से निकाला, तीन तलाक दिया

कानपुर (आरएनएस)। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने महिला और बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चकेरी थाने में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला के अनुसार उनका विवाह 4 फरवरी 2018 को अशरफ नगर बाबा नगर निवासी नईम अहमद से हुआ था। कुछ दिनों बाद से ही आरोपित अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा। विरोध करने पर मारपीट करता था। पीड़िता के अनुसार पति ने 14 फरवरी 2021 को उन्हें और उनके ढाई साल के बेटे को घर से निकाल दिया और तीन तलाक दे दिया। इसके बाद नईम ने दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई न कर उन्हें टरका दिया। नईम को पुलिस से शिकायत करने की बात पता चली तो 8 मार्च 2022 को वह अपने साथियों के साथ उनके घर आया और मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से शिकायत की।

यूक्रेन में मारे गए नवीन का पार्थिव शरीर लाया जाएगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अधिकारियों को यूक्रेन से नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले दिन में भारत की सुरक्षा तैयारियों और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की।

प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ समुद्री और हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों के नवीनतम विकास और विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को यूक्रेन में नवीनतम घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के विवरण के साथ-साथ भारत के पड़ोसी देशों के कुछ नागरिकों को यूक्रेन से निकाला गया।

पीएम मोदी ने अतीत में कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की थी क्योंकि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था और भारत ने छात्रों सहित फंसे हुए भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक बड़े पैमाने पर निकासी मिशन शुरू किया था। अब तक, सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों के माध्यम से युद्धग्रस्त देश से 20,000 से अधिक भारतीयों को वापस ला चुकी है।

कबीरधाम पुलिस को नक्सल उन्मूलन क्षेत्र में मिली बड़ी सफलता

- दो हार्डकोर ईनामी नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण

कवर्धा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण पुर्नवास नीति का सफल क्रियान्वयन के लिये अशोक जुनेजा पुलिस महानिदेषक छत्तीसगढ़, विवेकानंद सिन्हा अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक, विषेष आसूचना शाखा/नक्सल अभियान छत्तीसगढ़ के दिषा-निर्देषन एवं ओ.पी.पाल, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग के मार्ग दर्षन में चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान एवं छ.ग. शासन के आत्मसमर्पण पुर्नवास योजना के प्रचार-प्रसार की कार्यवाही निरंतर चलायी जा रही है। उक्त अभियान के दौरान जिले में सक्रिय नक्सली संगठन कान्हा भोरमदेव डिवीजन कमेटी अंतर्गत बोड़ला एरिया कमेटी के सक्रिय हार्डकोर ईनामी नक्सली- एरिया कमेटी कमाण्डर-डीव्हीसी करन एवं एरिया कमेटी सदस्य अनिता जो सितंबर 2019 में एरिया कमेटी को छोडक़र अपने गांव काकेकोरम थाना गंगालुर जिला बीजापुर चले गये थे तथा दोनों शादी कर साथ रह रहे हैं। जिसकी जानकारी मार्च 2020 एवं जुन 2021 में आत्मसमर्पित किये नक्सलियों के द्वारा दिये जाने से कबीरधाम पुलिस के द्वारा उक्त नक्सलियों की पतासाजी लगातार किया गया। स्थानीय सूत्रों एवं तकनीकी टीम के सहयोग से दोनो नक्सली करन एवं अनिता की जानकारी प्राप्त होने पर कबीरधाम पुलिस के द्वारा इनसे संपर्क स्थापित कर शासन की पुर्नवास नीतियों/सुझाव की जानकारी दिया गया। जिससे दोनों हार्डकोर ईनामी नक्सली दंपत्ति कबीरधाम पुलिस के माध्यम से शासन की पुर्नवास नीति से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा में जुडक़र अच्छी जीवन एवं सुरक्षित जीवन यापन करने आत्मसर्मपण हेतु तैयार होकर कबीरधाम पुलिस के सहयोग से पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग के समक्ष आत्मसर्मंपण किये हैं। आत्मसर्मंपण करने पर दोनों नक्सलियों को 10-10 हजार रूपये का प्रोत्साहन राषि त्वरित दिया गया, शासन की योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। उक्त समर्पण की कार्यवाही में ओ.पी. पाल पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग के मार्गनिर्देषन एवं डॉ. लाल उमेद सिंह, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिषा-निर्देष में कौषल किषोर वासनिक, उप पुलिस अधीक्षक नक्सल, सहायक उप निरीक्षक उदल मरकाम, संजीव तिवारी एवं उनके टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

लोगों को जल्द ही उनकी भाषा में भूमि अभिलेख मिलेंगे : गिरिराज सिंह

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने घोषणा की कि जल्द ही देश के लोग अपनी भूमि का रिकॉर्ड अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अप्रैल 2022 से बहुभाषी सॉफ्टवेयर शुरू करने की योजना बना रहा है। उसके बाद, भूमि रिकॉर्ड 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। मंत्री बजट में घोषित भूमि शासन सुधारों पर एक ई-पुस्तक का विमोचन करने के बाद बोल रहे थे, जिसका शीर्षक था श्वद्वश्चश2द्गह्म्द्बठ्ठद्द ष्टद्बह्लद्ब5द्गठ्ठह्य-क्कश2द्गह्म्द्बठ्ठद्द ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड (नागरिकों को सशक्त बनाना-भारत को सशक्त बनाना)। स्वदेशी रूप से विकसित एनजीडीआरएस (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली) सॉफ्टवेयर पर बोलते हुए, गिरिराज सिंह ने कहा कि एनजीडीआरएस सॉफ्टवेयर लगभग 4 करोड़ में तैयार किया गया है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को भू-राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि एनजीडीआरएस 13 राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिससे 22 करोड़ लोगों को लाभ होगा। अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 30.9 लाख दस्तावेज पंजीकृत किये जा चूके हैं, जिनसे 16 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

मंत्री ने कहा कि देश में यूएलपीआईएन (यूनीक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर) लागू होने के बाद गरीबों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता। रुक्कढ़्ढह्र को क्क्रह्र, आधार, भूमि अभिलेख, न्यायालय और बैंकिंग प्रणाली से जोडऩे से भूमि मामलों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से छुटकारा मिलेगा। अब तक, यूएलपीआईएन को 14 राज्यों में शुरू किया गया है। मंत्री ने राज्य सरकारों से लोगों के बीच भूमि सुधारों के बारे में जागरूकता फैलाने का भी अनुरोध किया।

ई-बुक की सामग्री विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन), राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) और भूमि अभिलेखों में भाषाई बाधा को तोडऩे के लिए-बहुभाषी भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के बाद भूमि अभिलेख सूचना और प्रबंधन में ठोस पारदर्शिता आई है। धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति लेनदेन को रोकने के लिए प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट भूमि पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रदान की जा रही है। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के अनुसार भारत के नागरिकों और भारत को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा, अद्यतन भूमि रिकॉर्ड, मुआवजे के भुगतान के समय को कम करेगा और भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास और पुनर्वास लाभ प्रदान करेगा। बहुभाषी भूमि रिकॉर्ड संभावित व्यक्तियों को उनकी क्षेत्रीय और मातृ भाषाओं में जानकारी की सुविधा प्रदान करेगा।

केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की एवं, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा तथा भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव सोनमोनी बोरा, इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारत में 675 दिनों में कोरोना के आए सबसे कम 36168 सक्रिय मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 2,503 नए मामले सामने आएं। यह अब तक के 680 दिनों में सबसे कम है इसके साथ भारत में वर्तमान में 38,069 सक्रिय रोगी हैं और यह 675 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों के 0.08 प्रतिशत हैं। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 4,377 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढक़र 4,24,41,449 हो गई है। 24 घंटों में कुल 5,32,232 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.90 करोड़ से अधिक (77,90,52,383) जांच की गई हैं।

साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है।

भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 180.19 करोड़ (1,80,19,45,779) से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,10,99,040 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।

नवा रायपुर में किसानों के आंदोलन व मृतक किसान की मौत पर मुआवजे का मामला सदन में गूंजा

- प्रतिपक्ष भाजपा सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मामले में आसंदी से चर्चा कराये जाने की मांग की
- विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को किया अग्राह्य
- स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य होने पर भाजपा सदस्यों ने किया हंगामा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सोमवार को प्रतिपक्ष भाजपा सदस्यों ने नया रायपुर में किसानों का आंदोलन एवं इस दौरान एक किसान की मौत का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। भाजपा सदस्यों ने इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराये जाने की मांग की। भाजपा सदस्यों ने आंदोलरत किसानों की मांग को पूरा करने के साथ मृत किसान के आश्रितों को 50 लाख रूपये मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया, जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया।

शून्यकाल में आज भाजपा सदस्यों ने नया रायपुर में पिछले करीब दो माह से आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन के साथ इस आंदोलन में एक किसान की मौत व मुआवजा के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। सबसे पहले भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने स्थगन प्रस्ताव की जानकारी सभापति को देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में आंदोलन कर रहे किसानों को विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर सभी कांग्रेस ने समर्थन किया था और उनसे वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद किसानों की हर मांग पूरी की जाएगी। लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि करीब दो माह से नया रायपुर में किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के साथ वहां एक किसान की मौत भी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ 4 लाख रूपये का मुआवजा की घोषणा करते है।

भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नया रायपुर से महज 2 किमी. दूर पर करीब 70 दिनों से किसानों का आंदोलन सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री उन किसानों से बात तक नहीं करते, बल्कि जहां किसान आंदोलन कर रहे है उसे कांजी हाऊस बना दिया गया है, जैसे किसान आतंकवादी हो। उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी बात करने वाली कांग्रेस सरकार सो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में हुए किसानों के आंदोलन पर बोलते है कि प्रधानमंत्री उनसे बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस जगह पर किसान धरना दे रहे थे वो जगह तो बहुत दूर थी, लेकिन नया रायपुर में मंत्रालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर किसान धरना दे रहे मुख्यमंत्री फिर उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे है। श्री अग्रवाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान एक किसान की मृत्यु हो गई। यह स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है क्योंकि गर्मी के दिनों में पिछले 70 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों में कई बुजुर्ग और कई बीमार लोग भी शामिल है। अगर किसानों को कुछ हुआ तो इस कलंक का टिका कांग्रेस सरकार पर लगेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश राज्य के खीरी लखीमपुर में हुई घटना में मृत किसानों को 50-50 लाख रूपये देते है, जबकि प्रदेश के मृत किसान परिवार को 04 लाख रूपये मुआवजा देते है। उन्होंने मांग की जब दूसरे राज्य के मृत किसान परिवार को 50 लाख रूपये दे सकते है तो प्रदेश के मृत किसान परिवार को 01 करोड़ रूपये देना चाहिए साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार पेपरों में विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करते है, लेकिन पिछले तीन साल में प्रदेश में 600 से अधिक किसानों ने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में एक किसान की जमीन का रकबा परिवर्तन करने का काम किया गया। 3.45 एकड़ खेती होती है 3 साल तक धान को बेचने का काम चलता रहा।